MPC के मिनट्स: दर वृद्धि के भीतर की बहस

खबरों में क्यों

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत RBI ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 5-7 अक्टूबर 2026 को हुई 63वीं बैठक के मिनट्स 21 अक्टूबर को प्रकाशित किए [प्राथमिक]। समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत की और नीतिगत रुख तटस्थ से बदलकर "कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" किया, पर मिनट्स बताते हैं कि रुख बदलने पर दो सदस्य सहमत नहीं थे [प्राथमिक]। (7 अक्टूबर के निर्णय का विश्लेषण इस साइट पर पहले से प्रकाशित है; यह लेख मिनट्स पर केंद्रित है।)

मिनट्स के प्रमुख तथ्य (RBI दस्तावेज़ से)

- CPI मुद्रास्फीति जुलाई के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2026 में 4.8 प्रतिशत; कोर मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत, कीमती धातुओं को छोड़कर कोर 2.9 प्रतिशत।
- CPI बास्केट में 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति वाली वस्तुओं का भारित हिस्सा अगस्त में लगभग 37 प्रतिशत रहा (मार्च में केवल 20 प्रतिशत था)।
- 2026-27 के लिए CPI पूर्वानुमान 5.2 प्रतिशत (अगस्त के 5.0 प्रतिशत के पूर्वानुमान से ऊपर); तिमाही-वार: Q2 4.9%, Q3 6.0%, Q4 5.7%; 2027-28 की पहली तिमाही 5.6 प्रतिशत; कोर पूर्वानुमान 4.4 प्रतिशत।
- **वैश्विक संदर्भ:** पश्चिम एशिया संघर्ष से कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव, प्रमुख केंद्रीय बैंकों का रुख सख्त; अमेरिकी फेड ने सितंबर में 25 आधार अंक बढ़ाए।
- "कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" का अर्थ (मिनट्स के अनुसार): निकट भविष्य में दर कटौती नहीं; आगे की कार्रवाई केवल वृद्धि या ठहराव हो सकती है।
- **दर-ढाँचा:** रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF/बैंक दर 5.75%। अगली बैठक 2-4 दिसंबर 2026।

सदस्यों की अलग-अलग राय (मिनट्स के अनुसार)

- डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह: दर वृद्धि के पक्ष में, पर रुख तटस्थ ही रखने के पक्ष में; तटस्थ से सख्ती की ओर बदलाव दर-वृद्धि के लंबे चक्र का संकेत बन सकता है।
- **श्री सौगत भट्टाचार्य:** वैश्विक वित्तीय स्थितियों में कड़कई, ऊर्जा कीमतें और G20 देशों में बढ़ती बॉन्ड यील्ड के हवाले से सख्ती के पक्ष में।
- **डॉ. पूनम गुप्ता (डिप्टी गवर्नर):** सही समय पर की गई कार्रवाई से मुद्रास्फीति-लक्ष्यण ढाँचे की विश्वसनीयता बनी है; 25 आधार अंक की वृद्धि उचित।
- बैठक की अध्यक्षता गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की; दर-प्रस्ताव सर्वसम्मत रहा, रुख के प्रश्न पर दो सदस्यों का मतभेद दर्ज हुआ।

विश्लेषण

मिनट्स दिखाते हैं कि मुद्रास्फीति अब केवल खाद्य-ईंधन तक सीमित नहीं है: इसका फैलाव (डिफ्यूज़न) बढ़ रहा है और लागत-वृद्धि उपभोक्ताओं तक पहुँच रही है (द्वितीय-चरण प्रभाव की आशंका)। मिनट्स स्वयं स्वीकार करते हैं कि आपूर्ति-पक्षीय मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति सीधे नहीं, बल्कि द्वितीय-चरण प्रभावों (मुद्रास्फीति-अपेक्षाएँ और फर्मों का मूल्य-निर्धारण व्यवहार) को रोककर काम करती है – यही सीमा इस बहस का केंद्र है। 4 प्रतिशत के लक्ष्य और 6 प्रतिशत की सहनशील सीमा (Q3 पूर्वानुमान 6.0%) के बीच RBI की चुनौती

है: वृद्धि को घात पहुँचाए बिना विश्वसनीयता बनाए रखना। (संदर्भ: सदस्य नागेश कुमार ने कहा कि FY27 वृद्धि-पूर्वानुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% किया गया है, यानी सख्ती का समर्थन करने के लिए वृद्धि की गुंजाइश देता है।)

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक: MPC की संरचना और मतदान; रेपो, SDF, MSF; मुद्रास्फीति-लक्ष्यण ढाँचा (4% ± 2%); RBI अधिनियम की धारा 45ZL (14वें दिन मिनट्स)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा (GS-3, अर्थव्यवस्था): "आपूर्ति-पक्षीय मुद्रास्फीति के युग में मौद्रिक नीति की सीमाएँ और भूमिका पर MPC के नवीनतम मिनट्स प्रकाश डालते हैं।" मिनट्स में दर्ज मतभेदों के आधार पर टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: संदर्भ दें - RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत प्रकाशित MPC की 63वीं बैठक (5-7 अक्टूबर 2026) के मिनट्स; सर्वसम्मति से रेपो 25 आधार अंक बढ़कर 5.50 प्रतिशत हुआ और रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' हुआ, पर रुख बदलने पर दो सदस्य सहमत नहीं थे।

मुख्य भाग में: मिनट्स के तथ्य रखें - CPI मुद्रास्फीति जुलाई के 4.5% से बढ़कर अगस्त में 4.8%, कोर 4.2% (कीमती धातुओं को छोड़कर 2.9%); 4% से अधिक मुद्रास्फीति वाली वस्तुओं का भारित हिस्सा मार्च के 20% से बढ़कर लगभग 37%; 2026-27 का CPI पूर्वानुमान 5.2% और Q3 का 6.0% - यानी फैलाव बढ़ रहा है। 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' का अर्थ (निकट भविष्य में कटौती नहीं; आगे केवल वृद्धि या ठहराव) समझाएँ। मतभेदों के आधार पर टिप्पणी करें - नागेश कुमार और राम सिंह का तर्क कि सख्त रुख लंबे दर-चक्र का संकेत बन सकता है; सौगत भट्टाचार्य का वैश्विक वित्तीय कड़कई, ऊर्जा कीमतें और G20 बॉन्ड यील्ड वाला तर्क; पूनम गुप्ता का तर्क कि समय पर कार्रवाई से मुद्रास्फीति-लक्ष्यण ढाँचे की विश्वसनीयता बनी है। सीमा स्पष्ट करें - मिनट्स स्वयं मानते हैं कि आपूर्ति-पक्षीय मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति सीधे नहीं, बल्कि द्वितीय-चरण प्रभावों (अपेक्षाएँ और मूल्य-निर्धारण व्यवहार) को रोककर काम करती है; 4% लक्ष्य और 6% सहनशील सीमा के बीच वृद्धि को घात पहुँचाए बिना विश्वसनीयता बनाए रखना ही चुनौती है।

निष्कर्ष में: निष्कर्ष दें - बढ़ते फैलाव के दौर में समय पर की गई सीमित सख्ती अपेक्षाओं को नियंत्रित रख सकती है, पर दर-वृद्धि के लंबे चक्र की आशंका और वृद्धि की लागत भी तौलनी होगी (संदर्भ: FY27 वृद्धि-पूर्वानुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% - नागेश कुमार)।

स्रोत और सीमाएँ

- [प्राथमिक] RBI, MPC (63वीं बैठक, 5-7 अक्टूबर 2026) के मिनट्स, 21 अक्टूबर 2026: लेख खोलें (rbi.org.in)
- [प्राथमिक] RBI, MPC समाधान (62वीं बैठक), 5 अगस्त 2026 (पूर्वानुमान 5.0% का संदर्भ): लेख खोलें (rbi.org.in)

सीमा: दोनों RBI दस्तावेज़ प्राथमिक रूप से पढ़े गए। सदस्यों के रुख उनके अपने कथनों का संक्षेप हैं। बाज़ार प्रतिक्रिया और 21 अक्टूबर के बाद की टिप्पणियाँ इस लेख में शामिल नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत RBI ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 5-7 अक्टूबर 2026 को हुई 63वीं बैठक के मिनट्स 21 अक्टूबर को प्रकाशित किए।

प्रश्न: अक्टूबर 2026 की MPC बैठक में रेपो दर और नीतिगत रुख पर क्या निर्णय हुआ?

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत RBI ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 5-7 अक्टूबर 2026 को हुई 63वीं बैठक के मिनट्स 21 अक्टूबर को प्रकाशित किए। समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत की और नीतिगत रुख तटस्थ से बदलकर "कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" किया, पर मिनट्स बताते हैं कि रुख बदलने पर दो सदस्य सहमत नहीं थे।

प्रश्न: मिनट्स में CPI और कोर मुद्रास्फीति की क्या स्थिति बताई गई है?

CPI मुद्रास्फीति जुलाई के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2026 में 4.8 प्रतिशत; कोर मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत, कीमती धातुओं को छोड़कर कोर 2.9 प्रतिशत। CPI बास्केट में 4 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति वाली वस्तुओं का भारित हिस्सा अगस्त में लगभग 37 प्रतिशत रहा (मार्च में केवल 20 प्रतिशत था)।

प्रश्न: MPC के किन सदस्यों ने नीतिगत रुख बदलने पर असहमति जताई?

डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह: दर वृद्धि के पक्ष में, पर रुख तटस्थ ही रखने के पक्ष में; तटस्थ से सख्ती की ओर बदलाव दर-वृद्धि के लंबे चक्र का संकेत बन सकता है। श्री सौगत भट्टाचार्य: वैश्विक वित्तीय स्थितियों में कड़कई, ऊर्जा कीमतें और G20 देशों में बढ़ती बॉन्ड यील्ड के हवाले से सख्ती के पक्ष में।